बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

# सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 57 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 09 दिसम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

### दिल्ली में मर्डर से सनसनी: शकरपुर में युवक की हत्या, तो वहीं मदनपुर खादर में हुई चाकूबाजी; दो की गई जान

नई दिल्ली । पूर्वी दिल्ली में एक हत्या के मामले से इलाके में सनसनी फैल गई। शकूरपुर इलाके में बीती शाम को हुई एक सनसनीखेज घटना में 22 वर्षीय युवक देव कुमार को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 103 (1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस को बीती रविवार शाम करीब 5:28 बजे राम टेंट हाउस, मेन मार्केट, शकूरपुर के पास चाकूबाजी की घटना की सूचना मिली। कॉल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसके भाई पर हमला किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां खून बिखरा हुआ पाया गया और लोगों की भीड़ जमा थी।

## प्रियंका का सवाल- वंदे मातरम् पर आज बहस क्यों, जितने साल मोदी पीएम, उतने साल नेहरू जेल में रहे

नई दिल्ली । केरल की वायनाड सीट से चुनकर लोकसभा पहुंचीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी वंदे मातरम पर चर्चा में भाग लिया। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि संसद में इस समय ये चर्चा इसलिए कराई गई, क्योंकि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। प्रियंका गांधी ने संसद में आगे कहा कि वंदे मातरम केवल भावना नहीं, बल्कि देश की आजादी की लड़ाई की ताकत और नैतिकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस गीत ने ब्रिटिश साम्राज्य को भी झुकने पर मजबूर किया था। प्रियंका ने कहा कि वंदे मातरम नाम लेते ही स्वतंत्रता संग्राम की यादें और उसका साहस सामने आ जाता है। उन्होंने आगे कहा कि 1930 के दशक में सांप्रदायिक की राजनीति उभरी तब ये गीत विवादित होने लगा. उन्होंने आगे कहा कि 1937 में नेताजी कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कर रहे थे. 20 अक्तूबर का लेटर उन्होंने सुनाया, लेकिन इससे पहले उन्होंने नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी, इसका पीएम मोदी ने जिक्र नहीं किया.

**हम देश के लिए है, आप चुनाव के लिए है- प्रियंका गांधी**

प्रियंका ने कहा कि हम देश के लिए है, आप चुनाव के लिए है. 17 अक्टूबर को चिट्ठी के जवाब में नेहरू ने 20 अक्तूबर की चिट्ठी में लिखा- मैंने तय किया है कि मैं 25 अक्टूबर कोलकाता आऊंगा, टैगोर से मिलूंगा. 28 अक्तूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम् को राष्ट्रगीत घोषित किया. इस कार्यसमिति की बैठक में सभी महापुरुष मौजूद थे. सभी इस प्रस्ताव से खुश थे. सहमत थे.

**वंदे मातरम पर बहस की जरूरत क्यों? प्रियंका गांधी का सवाल**

संसद में वंदे मातरम पर हो रही बहस के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी। उन्होंने कहा कि यह गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा रहा है और 75 साल से आजाद भारत में जनता के दिलों में बसता आया है। प्रियंका ने पूछा कि आज इस पर बहस कर सरकार क्या साबित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष को जनता की जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए, न कि ऐसे मुद्दों पर विवाद खड़ा करना चाहिए।

**मोदी जितने साल से पीएम हैं, उतने साल तो नेहरू ने जेल में बिताए**

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में वंदे मातरम पर चल रही बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान सभा द्वारा स्वीकृत वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना रवींद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेताओं का अपमान है। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री 12 साल से देश चला रहे है, और यह वही अवधि है जितने साल पंडित नेहरू ने आजादी की लड़ाई में जेल में बिताए थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि पंडित नेहरू ने 12 साल जेल में रहने के बाद देश का 17 साल तक नेतृत्व किया था। उन्होंने भाजपा पर नेहरू को बार-बार निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि सरकार को नेहरू पर चर्चा करनी है तो स्पीकर की अनुमति लेकर लंबी बहस करा ले। लेकिन उन मुद्दों पर बात भी जरूरी है, जिनके लिए जनता प्रतिनिधियों को संसद भेजती है। उन्होंने सवाल उठाया कि बेरोजगारी, गरीबी और प्रदूषण जैसे असली मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है।



**आज के पीएम पहले जैसे नहीं रहे- पीएम**

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार का ध्यान न वर्तमान पर है, न देश के भविष्य पर। उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार इतिहास में उलझाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी भी अब पहले जैसे नहीं रहे और उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही है।

उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के कई लोग भी इससे सहमत है, इसलिए वे चुप रहते है। प्रियंका ने कहा कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं से घिरी है, लेकिन सरकार के पास समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों पर चर्चा का समय भी जल्द आएगा और तब विपक्ष अपनी बात मजबूती से रखेगा।

**वंदे मातरम देशभक्ति जगाने वाला गीत- प्रियंका गांधी**

प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि वंदे मातरम ऐसा गीत है, जो देश के लिए बलिदान की भावना जगाता है। उन्होंने बताया कि 1896 में रवींद्रनाथ टैगोर ने यह गीत गाया था और 1905 में वे इसी गीत के साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में उतरे थे। प्रियंका ने कहा कि 1930 के दशक में सांप्रदायिक राजनीति बढ़ने पर यह गीत विवादों में आया। उन्होंने कहा कि नेताजी ने 1937 में नेहरू को जो पत्र लिखा था, उसका जिक्र पीएम मोदी ने नहीं किया।

**पीएम अच्छे वक्ता, लेकिन तथ्य कमजोर- प्रियंका गांधी**

लोकसभा में प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण प्रभावी था, लेकिन तथ्यों पर कमजोर रहा। उन्होंने कहा कि पीएम ने वंदे मातरम के इतिहास का जिक्र करते समय कुछ तथ्य छोड़ दिए। प्रियंका ने बताया कि 1896 में रवींद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के अधिवेशन में यह गीत गाया था।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वंदे मातरम की शुरुआत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दो छंदों से की थी और 1882 में उपन्यास आनंदमठ में इसके चार और छंद जोड़ दिए गए। प्रियंका ने कहा कि वह सदन में तथ्य को तथ्य की तरह रखना चाहती है।

**देश कमजोर हो रहा- प्रियंका गांधी**

संसद में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार बार-बार इतिहास में उलझाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है और वर्तमान व भविष्य की ओर नजर नहीं डाल रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अब पहले जैसे नहीं रहे और सरकारी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। प्रियंका ने दावा किया कि सत्ता पक्ष के कई लोग भी इस बात से सहमत है, इसलिए वे चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से घिरी है, पर सरकार के पास समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव पर चर्चा का समय आएगा, तब विपक्ष खुलकर बोलेगा।

## दिल्ली में बढ़ती ठंड कोई बेघर सड़क पर न सोएगा, रैन बसेरों पर रेखा गुप्ता सरकार सख्त

नई दिल्ली । दिल्ली में बढ़ती ठंड को देखते हुए शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने अधिकारियों से दिल्ली में बने रैन बसेरों की स्थित पर अपडेट लिया. इस दौरान उन्होंने डूसिब (दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड) के अधिकारियों से बात की और बेघर तथा जरूरतमंद लोगों के लिए बनाई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया. मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि सर्दियों के दौरान दिल्ली में कोई भी गरीब या बेघर व्यक्ति सड़कों पर खुले आसमान के नीचे रात न बिताए. उन्होंने बताया कि जरूरत को देखते हुए दिल्ली में 200 से ज्यादा अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं.

जहां लोगों को बिस्तर, गरम कंबल, स्वच्छ पानी, भोजन, सफाई, हीटर और सुरक्षा की सुविधाएं दी जा रही हैं. आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में रैन बसेरों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं. ताकि हर व्यक्ति को समय पर खाना, कंबल और सुरक्षित जगह मिल सके. उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त कंबल और साफ-सुथरे आरामदायक बिस्तर उपलब्ध कराए जाएं. रैन बसेरों में सफाई, रोशनी, सुरक्षा और आग से बचाव के उपकरण तय मानकों के मुताबिक होने चाहिएं. महिला रैन बसेरों के लिए मंत्री ने विशेष निर्देश दिए कि वहां महिलाओं की गोपनीयता और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए. इसके अलावा, सड़कों पर सो रहे लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू टीमें सक्रिय रहें. ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड में परेशान न हो. इधर सामाजिक कार्यकर्ता भावेश पिपलिया ने सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे .

उन्होंने आरोप लगाया था कि बीते शुक्रवार की रात 10 बजे से शनिवार सुबह 3:30 बजे तक वह करीब 21 जगहों पर घूमे, जहां 50 लोग खुले आसमान के नीचे ठंड में सोते मिले. उन्होंने मदद के लिए कॉल भी किया. लेकिन केवल एक व्यक्ति को ही रैन बसेरे ले जाया जा सका. बाकी 49 लोग खुले में ही सोते रहे. उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में 10 से ज्यादा बेघर लोगों की मौत हुई है, जिनके शरीर पर किसी तरह की चोट नहीं मिली. ऐसे में शक है कि वे ठंड की वजह से मरे हों. इन आरोपों पर मंत्री आशीष सूद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन आरोपों कि जांच हो अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी लापरवाही करता पाया जाय तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा सरकार की प्राथमिकता है कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति ठंड में खुले आसमान के नीचे न सोए अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाय तो उसे रेस्क्यू टीम रैन बसेरे में पहुंचाए. दिल्ली में सर्दी लगातार बढ़ रही है

और ऐसे में रैन बसेरों की व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं और सरकार की कोशिशें भी जारी हैं. अब उम्मीद है कि जरूरतमंद लोगों को समय पर सही मदद मिल सकेगी.

## पीएम मोदी बिहार के एनडीए सांसदों से मिले, दी ये नसीहत

नई दिल्ली । पीएम नरेन्द मोदी ने सोमवार को बिहार से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों से हाल में संपन्न राय विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन की शानदार जीत के बाद लोगों के कल्याण के लिए और अधिक उत्साह के साथ काम करने का आह्वान किया। नरेन्द मोदी ने कहा, बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने राजग सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को उस समय यह संदेश दिया, जब वे (राजग सांसद) उन्हें (मोदी को) बिहार चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन की भारी जीत की बधाई देने के लिए दिल्ली आए थे। बैठक के बाद शांभवी ने पत्रकारों से कहा, हमने बिहार में शानदार नेतृत्व और प्रचार अभियान के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी तथा उनका आभार जताया, जिसके कारण हमारे चुनाव अभियान को मजबूत गति मिली थी। प्रधानमंत्री ने हमें याद दिलाया कि बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। शांभवी ने बताया कि मोदी ने सांसदों से बिहार के लोगों के कल्याण के लिए और अधिक उत्साह के साथ काम करने का आह्वान किया, क्योंकि सभी के लिए समावेशी विकास राजग की स्पष्ट प्राथमिकता है, फिर चाहे वे किसी भी वर्ग के हों। शांभवी के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने राजग सांसदों से कहा कि वे नकारात्मकता, घृणा और झूठ के बजाय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। सूत्रों के अनुसार, मोदी ने बिहार के राजग सांसदों को याद दिलाया कि उनका असली काम चुनाव के बाद शुरू होता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने गठबंधन के प्रत्येक सहयोगी दल से बातचीत की और बिहार में राजग की जीत के महत्व पर जोर दिया। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए पिछले महीने हुए चुनाव में राजग ने 202 सीट पर जीत दर्ज की, जिससे जनता दल यूनाइटेड (जदयू) प्रमुख नीतीश कुमार के 10वीं बार राय का मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। राजग को मिली कुल 202 सीट में से 89 पर भाजपा, 85 पर जदयू, 19 पर लोजपा (रामविलास), पांच पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) और चार पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की।

## इंडिगो संकट पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट! यात्रियों की मदद संबंधी याचिका पर 10 दिसंबर को होगी सुनवाई

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका को 10 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसमें इंडिगो द्वारा सैकड़ों उड़ानें रद्द किए जाने से प्रभावित यात्रियों को सहायता और टिकट के पैसे वापस करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष सोमवार को याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्होंने इंडिगो संकट के मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा, ''कई लोग फंसे हुए हैं। हवाई अड्डों पर जमीनी हालात अमानवीय हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अदालत हवाई अड्डों पर फंसे लोगों के लिए इंडिगो और जमीनी स्तर पर सहायक कर्मचारियों को आदेश देगी। पैसे वापस करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। जब अदालत ने कहा कि सरकार इस मामले में पहले ही कुछ निर्देश दे चुकी है, तो वकील ने सकारात्मक जवाब दिया। पीठ ने कहा कि जनहित याचिका बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी। सूत्रों ने 'पीटीआई-भाषा को बताया कि सोमवार को दिल्ली और बेंगलुरु हवाई अड्डों से इंडिगो की 250 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं क्योंकि संकटग्रस्त विमानन कंपनी के उड़ान संचालन में व्यवधान सातवें दिन भी जारी रहा। उन्होंने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर 134 उड़ानें रद्द की गईं, जिनमें 75 प्रस्थान और 59 आगमन उड़ानें थीं। वहीं, बेंगलुरु हवाई अड्डे पर एयरलाइन ने 127 सेवाएं रद्द कीं।

## उच्चतम न्यायालय ने इंडिगो की उड़ानें रद्द किए जाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने इंडिगो की ओर से सैकड़ों उड़ानें रद्द किए जाने के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप के अनुरोध वाली याचिका पर सोमवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि केंद्र ने स्थिति का संज्ञान लिया है और इसके समाधान के लिए कदम उठाए हैं। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह इस तथ्य से अवगत है कि लाखों लोग विभिन्न हवाई अड्डों पर परेशानी झेल रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, यह एक गंभीर मामला है। लाखों लोग हवाई अड्डों पर परेशानी झेल रहे हैं। हम जानते हैं कि भारत सरकार ने समय पर कार्रवाई की है और इस मुद्दे का संज्ञान लिया है। हम समझते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी और अन्य महत्वपूर्ण समस्याएं हो सकती हैं। एक वकील ने इस मुद्दे का उल्लेख किया और कहा कि पिछले कुछ दिनों में इंडिगो द्वारा कई उड़ानें रद्द की गई हैं और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा, उड़ानों के रद्द होने की सूचना यात्रियों को नहीं दी गई।'' उन्होंने यह भी कहा कि देशभर के 95 हवाई अड्डों पर लगभग 2,500 उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। सूत्रों ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान सातवें दिन भी जारी रहा और सोमवार को विमानन कंपनी ने दिल्ली और बेंगलुरु हवाई अड्डों से 250 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं। दिल्ली हवाई अड्डे से कुल 134 उड़ानें रद्द की गईं, जिनमें रवाना होने वाली 75 और पहुंचने वाली 59 उड़ानें शामिल हैं।

## दिल्ली एयरपोर्ट पर लगेज के लिए मची है अफरातफरी, यात्री बोले- कस्टमर केयर से संपर्क तक नहीं हो रहा

नई दिल्ली।

यात्रियों के लिए इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से जुड़ी परेशानी भले ही धीरे-धीरे कम हो रही है, लेकिन लगेज की बात करें तो यहां अभी भी मारामारी की स्थिति है। कई ऐसे भी लोग हैं, जो एक, दो या तीन नहीं बल्कि पूरे पांच दिन बीत जाने के बाद भी लगेज के इंतजार में हैं। इनमें से कई जहां अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद इंतजार कर रहे हैं तो कई ऐसे हैं जो अपने स्वजन को रोजाना एयरपोर्ट भेजकर बस किसी तरह लगेज पाने की जुगत में हैं।

**लगेज घर पहुंचाने का किया वादा**

गुजरात के सूरत में रहने वाले किरण व विभा गांधी तीन दिसंबर को वाराणसी से खजुराहो होते हुए आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां से उसी दिन इनकी उड़ान सूरत के लिए थी। मगर तीन तारीख को उड़ान रद्द हुई। बाद में इसे रिशेड्यूल करके पांच दिसंबर किया गया लेकिन पांच तारीख को एयरपोर्ट पहुंचने में पता चला कि टर्मिनल के भीतर इंडिगो के यात्रियों को प्रवेश करने ही नहीं दिया जा रहा है।

कस्टम केयर से कई बार की कोशिश के बाद इन्हें आश्वस्त किया गया कि आपका लगेज आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा।

**कुछ लगेज हो गए गायब**

उड़ान कब मिलेगी, इसका कोई उत्तर नहीं मिला। बाद में किरण ने किसी तरह सामान्य किराए से तीन गुना अधिक किराया देकर बस की टिकट अहमदाबाद के लिए ली। बदकिस्मती देखिए, यहां भी लेटलतीफी ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। तय समय से करीब तीन घंटे बाद बस आई। खैर किसी तरह अहमदाबाद पहुंचे, लेकिन दिल्ली में रहते हुए इन्होंने अहमदाबाद से सूरत के लिए जो टैक्सी बुक की थी, वह तय समय के बीतते ही निकल गई। यहां भी इन्हें जबरदस्त घाटा हुआ। बाद में किसी तरह अहमदाबाद से सूरत रविवार को सुबह साढ़े नौ बजे पहुंचे। उम्मीद थी कि लगेज पहुंच गया होगा लेकिन यह क्या लगेज नहीं इन्हें लगेज की कुछ तस्वीर वॉट्सएप पर मिलीं। पूछा गया कि यह लगेज आपका ही है न। किरण बताते हैं कि जो लगेज की तस्वीर भेजी गई है, वह इन्हीं की है लेकिन कुछ लगेज गायब हैं। इसके बाद बार-बार की कोशिश के बाद भी इंडिगो के कस्टमर केयर से इनका संपर्क नहीं हो पा रहा है।

**कहा-इंडिगो ने किया यात्रियों से धोखा**

किरण बताते हैं कि इंडिगो प्रकरण ने पूरे विमानन प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। इंडिगो को दिसंबर की शुरुआत से ही पता चल गया होगा कि यह समस्या आने वाली है, लेकिन उसने इस समस्या से नियामक एजेंसियों व ग्राहकों को अवगत कराने की जरुरत नहीं समझी। यह इंडिगो की नैतिकता व उसकी पेशेवर सोच पर सवाल खड़े करता है। पहले आपने ग्राहकों से मुंह मोड़ा और अब उनका लगेज वापस नहीं दे रहे हो, यह सरासर धोखा है। आइजीआई टर्मिनल एक पर एयरलाइन के टिकट काउंटर के पास फ्लाइट के इंतजार में कुछ बैठे कुछ वहीं आराम करते यात्री। चंद्र प्रकाश मिश्र ।

किरण की पत्नी विभा बताती हैं कि लगेज में उनकी जरूरी दवाइयां हैं। वाराणसी मंदिर का प्रसाद है, जो उन्होंने अपने स्वजन व पड़ोसियों के लिए खरीदा था, अब उसका क्या होगा।

यह आस्था के साथ भी खिलवाड़ है। यात्रियों को जो परेशानी हुई और जो हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदार को क्या सजा मिली, यह जानने का हम सभी को हक है। हम लोग अब शायद ही इंडिगो की उड़ानों पर भरोसा कर सकें। बता दें कि किरण व विभा गुजरात के सूरत से तीर्थाटन के लिए निकले यात्रियों के जत्थे में शामिल लोग हैं। जत्थे में इनके साथ सूरत के करीब 15 लोग और थे। इनमें से किसी को भी लगेज अभी तक नहीं मिला है।

टर्मिनल एक के टिकट काउंटर को कई लोग इंक्वायरी काउंटर समझते हैं। यहां कतार में लगे लोगों में कई ऐसे हैं जो केवल और केवल लगेज के बारे में जानकारी लेने आए हैं। लंबे समय कतार में खड़े होने के बाद जब ऐसे लोगों की बारी आती है तो उन्हें कहा जाता है कि लगेज के बारे में वे कुछ भी नहीं बता सकते। ऐसे लोगों का सवाल है कि आखिर हमें जानकारी कहां मिलेगी? सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हमें टर्मिनल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है। ऐसे में बेहतर तो यह होता कि इंडिगो एक सहायता काउंटर फोरकोर्ट एरिया में खोले जहां लोगों को अपने सवालों का उत्तर मिल सके। भले ही लगेज नहीं मिले, लेकिन लगेज कहां है, सुरक्षित है या नहीं, इसका तो पता चले।

# रिटायरमेंट आयु वृद्धि पर राष्ट्रीय बहस -संभावित सरकारी प्रस्ताव, कर्मचारियों की उम्मीदें और युवाओं की चिंताओं का समग्र विश्लेषण

**भारत** सरकार द्वारा कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर गंभीरता से संभावित विचार किए जाने की हालिया जानकारी ने पूरे देश की मीडिया में एकव्यापक बहस को जन्म दे दिया है। यह मुद्दा केवल सरकारी व्यवस्था या नौकरशाही तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के विशाल श्रम बाजार, आर्थिक संरचना, पेंशन प्रणाली, युवाओं की रोजगार संभावनाओं और कार्यस्थल की दीर्घकालिक नीतियों पर गहरा प्रभाव डालता है। वैश्विक संदर्भ में भी यदि देखें तो बढ़ती उम्र,जीवन प्रत्याशा और पेंशन-भार को देखते हुए रिटायरमेंट आयु में बदलाव किए है। ऐसे में भारत का यह कदम न केवल आर्थिक अनिवार्यता का संकेत है, बल्कि एक परिवर्तनशील सामाजिक- आर्थिक ढांचे की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत भी देता है।एडवोकेट किशन सम्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि केंद्रीय सरकार के स्तरपर रिटायरमेंट की उम्र को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का विचार महज किसी एक प्रशासनिक या वित्तीय गणना का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई व्यापक कारण मौजूद हो सकते है? पिछले एक दशक में भारत में जीवन प्रत्याशा लगातार बढ़ी है, वरिष्ठ कर्मचारियों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और कई क्षेत्रों में अनुभव -आधारित कार्य-प्रदर्शन की मांग बढ़ी है। जिन देशों में जनसंख्या वृद्ध हो रही है,वहां रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी आम हो चुकी है,जैसे फ्रांस, जापान, जर्मनी, अमेरिका और चीन। भारत में भी यह मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है, क्योंकि देश की कार्यबल संरचना में तेजी से बदलाव हो रहा है।इसके अलावा, सरकार पर पेंशन-व्यय और सामाजिक- सुरक्षा योजनाओं का बोझ बढ़ता जा रहा है। एक बड़ी संख्या में कर्मचारी अगले 10-15 वर्षों में रिटायर होने वाले है। यदि एक साथ भारी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त होते है, तो इससे न केवल सरकारी तंत्र में खिंचाव आता है,बल्कि अनुभवी मानव- संसाधन की कमी भी पैदा होती है। इसी संदर्भ में रिटायरमेंट आयु दो वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव कई स्तरों पर महत्वपूर्ण और तार्किक प्रतीत होता है।यह आर्टिकल सोशल मीडिया में चल रही तार्किक बस पर आधारित है सटीकता मेंइंडेड की संबंध नहीं है। साथियों बात कर हम सरकार का प्रस्ताव- 60 से 62 वर्ष रिटायरमेंट आयु एक नीतिगत परिवर्तन इसको समझने की करें तो, सरकार द्वारा संकेत दिए गए संभावित प्रस्ताव में रिटायरमेंट आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की संभावना जताई गई है। यह प्रस्ताव केंद्रीय कर्मचारियों, राज्यों के कर्मचारियों,सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों, और कई अर्ध-सरकारी संस्थाओं कोप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा।सरकार के इस कदम के पीछे प्रमुख तर्क इस प्रकार हो सकते है (1) अनुभवी कर्मचारियों को बनाए रखना-प्रशासन से लेकर टेक्निकल क्षेत्रों तक, कई विभाग ऐसे है जहां अनुभव सीधे कार्य-कुशलता से जुड़ा होता है। वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों का सेवाकाल बढ़ाने से नीतिगत निरंतरता बनी रहती है और प्रशिक्षण पर दबाव घटता है।(2) पेंशन-भार कम करना-दो वर्ष अतिरिक्त सेवा का अर्थ है कि कर्मचारी दो साल और योगदान देंगे, जबकि सरकार को पेंशन का बोझ दो साल बाद उठाना होगा। इससे राजकोष पर तत्काल दबाव कम होगा। (3) कर्मचारियों के वित्तीय जीवन को स्थिरता- महंगाई बढ़ता शहरी जीवन-यापन खर्च, स्वास्थ्य- देखभाल के बढ़ते खर्च और लंबी आयु इन सभी के लिए लंबी आयु तक सेवा कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा देती है।(4) पोस्ट- रिटायरमेंट आर्थिक तनाव कम करना-कई अध्ययन बताते है कि बड़ी संख्या में लोग रिटायरमेंट के तुरंत बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते है। दो वर्ष का अतिरिक्त समय उनके लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करता है। साथियों बात अगर हम कर्मचारियों की उम्मीदें और वित्तीय लाभ- दो साल की अतिरिक्त सेवा क्यों महत्वपूर्ण है इसको समझने की करें तो,भारत में 60 वर्ष के बाद लोग केवल उम्र के हिसाब से बूढ़े माने जाते है, स्वास्थ्य के हिसाब से नहीं। आधुनिक कार्य वातावरण में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग पूरी तरह सक्रिय और कुशल होते है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए यह निर्णय कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकता है (1)दो वर्ष का अतिरिक्त वेतन -जीवन भर की आय पर बड़ा असर सबसे बड़ा लाभ सीधे वेतन से जुड़ा है। कर्मचारियों को दो वर्ष अधिक वेतन मिलने का मतलब है-अधिक बचत,अधिक निवेश, सामाजिक सुरक्षा राशि में बढ़त, रिटायरमेंट के बाद बेहतर आय-स्रोत,विशेषकर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह बढ़ोतरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। (2) पेंशन और ग्रेच्युटी में वृद्धि-पेंशन का निर्धारण आखिरी वेतन और कुल सेवा अवधि के आधार पर होता है।दो वर्षों की अतिरिक्त सेवा से-पेंशन राशि बढ़ जाएगी, ग्रेच्युटी की कुल गणना में वृद्धि होगी,कम्युटेशन (एकमुश्त राशि) बढ़ेगी,इससे रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता काफी मजबूत होगी। (3) ईपीएफओ में अधिक योगदान जो कर्मचारी ईपीएफ के दायरे में आते है, उन्हें दो वर्षों तक एम्प्लायर और एम्प्लॉयी दोनों का योगदान मिलता रहेगा।इससे-रिटायरमेंट कॉर्पस मजबूत होगा,ब्याज के रूप में अधिक राशि का लाभ मिलेगा,लंबे समय तक सुरक्षित कैश रिज़र्व बनेगा (4) स्वास्थ्य सुरक्षा और मेडिकल कवरेज-सेवा अवधि बढ़ने से कई कर्मचारियों को-सरकारी चिकित्सा सुविधाएँ,स्वास्थ्य बीमा सीजीएचएस लाभ-दो वर्ष अधिक मिलेंगे।यह सेवानिवृत्ति के बाद होने वाले स्वास्थ्य खर्चों को काफी कम कर सकता है।

(5) 2025-2026 में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को राहत- ये कर्मचारी जो जल्द ही रिटायर होने वाले है, उनके लिए यह प्रस्ताव राहत का संदेश है। उन्हें अचानक आर्थिक योजना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे दो वर्षों तक परिवार की वित्तीय सुरक्षा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। साथियों बात अगर हम सरकारी तर्क- कार्यस्थल पर दक्षता और अनुभव का योगदान इसको समझने की करें तो,सरकार का तर्क है कि वरिष्ठ कर्मचारियों के पास वह अनुभव, जमीनी समझ और नीतिगत परिपक्वता होती है जिसे अचानक प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।कई क्षेत्रों में जैसे-आयुर्विज्ञान, न्यायपालिका, अनुसंधान इंजीनियरिंग,सार्वजनिक प्रशासन में उम्र ज्ञान का पर्याय होती है।इन क्षेत्रों में 60 वर्ष की आयु में क्षमता समाप्त नहीं होती, बल्कि कई मामलों में इसी उम्र में व्यक्तियों का प्रदर्शन सबसे परिपक्व होता है।इसके अलावा, कई युवा अधिकारी अनुभवहीन होने के कारण उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर कार्य-क्षेत्र में दक्ष बनते है।यदि सभी वरिष्ठ कर्मचारी एक साथ रिटायर होने लगेंगे, तो संस्थागत निरंतरता टूट सकती है। इसलिए, रिटायरमेंट आयु बढ़ाना रणनीतिक रूप से प्रशासनिक मजबूती का उपाय भी माना जा रहा है। साथियों बात अगर हम युवाओं की चिंता- रोजगारअवसरों पर संभावित प्रभाव इसको समझने की करें तो,इस निर्णय कायुवाओं पर प्रभाव बहस का प्रमुख केंद्र है।युवा वर्ग विशेष रूप से इस बात को लेकर चिंतित है कि (1) नई भर्ती में देरी हो सकती है-यदि वरिष्ठ पदों पर बैठे लोग दो वर्ष और सेवा में रहेंगे तो,नए पद देर से खाली होंगे, प्रमोशन चैन धीमा पड़ेगा,युवा उम्मीदवारों की नियुक्ति की गति कम हो सकती है,यह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए चिंता का विषय है। (2) पदों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है- कई विभागों में भर्ती पदों की संख्या स्वतःरिटायरमेंट पर निर्भर होती है।रिटायरमेंट आयु बढ़ने का अर्थ है-भर्ती चक्र धीमा, रिक्तियां कम,नए रोजगारअवसरों में संकुचन (3) करियर की शुरुआत में देरी-भारतीय युवा अक्सर 25-28 वर्ष की उम्र में नौकरी की तैयारी में लगे होते है। यदि भर्ती देर से होगी तो,उनके करियर की शुरुआत पीछे चली जाएगी,सामाजिक और पारिवारिक दबाव बढ़ेगा,आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत भी काफी देर से होगी (4) निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और कठिन हो सकती है- सरकारी नौकरियों में देरी का अर्थ है कि अधिक युवा निजी क्षेत्र में धकेले जाएंगे, जिससे उस क्षेत्र में भी प्रतियोगिता बढ़ जाएगी। साथियों बात अगर हम सरकार का दृष्टिकोण- संतुलन बनाते हुए नीति लागू करने की कोशिश इसको समझने की करें तो, सरकार की ओर से संकेत दिया गया है कि यह नीति जल्दबाजी में लागू नहीं की जाएगी बल्कि चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने पर विचार होगा। इसके संभावित विकल्प है-विभागवार रिटायरमेंट आयु में वृद्धि,कुछ पदों पर फिलहाल 60 वर्ष ही बनाए रखना,युवाओं के लिए, समानांतर विशेष भर्ती मिशन,नए पद सृजित करके रिक्तियों की कमी दूर करना,सरकार का मानना है कि युवाओं और वरिष्ठ दोनों वर्गों के हितों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।इसलिए, इस नीति से पहले व्यापक दिशानिर्देश जारी होने की संभावना है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि,भर्ती प्रक्रिया बाधित न हो,युवाओं के लिए वैकल्पिक अवसर बनें,वरिष्ठ कर्मचारियों का बिना व्यवधान योगदान देने का अवसर मिले । साथियों बात अगर हम आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव, विस्तृत विश्लेषण के दृष्टिकोण से देखे तो (1) आर्थिक प्रभाव- सरकारी पेंशन व्यय कम होगी सार्वजनिक धन का बेहतर प्रबंधन,वरिष्ठ कर्मचारियों के माध्यम से आर्थिक स्थिरता (2) सामाजिक प्रभाव-परिवारों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी,वरिष्ठ नागरिक समाज में अधिक सक्रिय रहेंगे,वृद्धावस्था आश्रय और पेंशन आधारित निर्भरता कम होगी ।

**सम्पादकीय...**

## मणिबेन की डायरी

सब जानते हैं कि भगवा पार्टी वाले अपने निंदा विरोधियों पर ही नहीं, दिवंगत विरोधियों तक पर यह हथियार चलाते आए हैं, जैसे सबसे ज्यादा मौकों पर जवाहरलाल नेहरू पर और उससे थोड़ा कम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी वगैरह पर भी। पेटेंट उनके नाम हो न हो, पर परंपरा से इस्तेमाल करते आने से तो माफी मंगवाने पर भगवा पार्टी का अधिकार बनता ही है। फिर विरोधी किस मुंह से राजनाथ सिंह से माफी की मांग कर रहे हैं? सच पूछिए तो राजनाथ सिंह से विरोधियों का माफी की मांग करना तो और भी गलत है। कहने वाले कहते हैं कि वह नाम के ही रक्षा मंत्री हैं। वर्ना रक्षा तो वह खुद अपनी नहीं कर पा रहे हैं और हर रोज मार्गदर्शक मंडल की ओर एकाध-कदम खिसक ही जाते हैं। इससे बचने के चक्कर में वह पार्टी और सरकार में किसी के मांगे बिना भी, परमानेंटली माफी मांगने की मुद्रा में ही रहते हैं। पर कोई पैंतरा काम नहीं कर रहा; नेहरू के लिए माफी मांगने की मांग करना भी। लेकिन, क्या इसीलिए विरोधियों को राजनाथ सिंह के प्रति थोड़ा ज्यादा उदार नहीं होना चाहिए? जब घर में ही उनकी स्थायी मुद्रा माफी मांगने की है, तो क्या विरोधियों को इससे कुछ अलग नहीं करना चाहिए? अन्याय कहीं भी हो, विरोधियों का उसका विरोध करना तो बनता है। विरोधी, इस मामले में विरोध का अपना धर्म कैसे भूल सकते हैं? फिर राजनाथ सिंह से विरोधी माफी की मांग किसलिए रहे हैं? कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने यह झूठ बोला है कि जवाहरलाल नेहरू, सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। सरदार पटेल ने ऐसा नहीं होने दिया। इससे खिसियाकर नेहरू जी ने सोमनाथ के मंदिर के निर्माण के लिए पैसा देने से मना कर दिया, वगैरह। यह सरासर गलत है बल्कि झूठ है। और तो और विरोधी, सरदार की बेटी मणिबेन डायरी के पन्ने निकाल लाए हैं और उसे राजनाथ सिंह की बात के झूठ होने का सबूत बता रहे हैं। बेशक, मणिबेन ने अपनी डायरी में जो लिखा है, वह झूठ क्यों होने लगा? जरूर तब वही हुआ होगा, जो मणिबेन ने डायरी में लिखा है। न नेहरू जी ने सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाने चाही होगी और न सरदार पटेल ने उसका विरोध किया होगा। माना कि सरदार पटेल बहुत बार नेहरू जी का विरोध करते थे, पर सरदार भी विरोध तो तभी कर सकते थे, जब नेहरू जी बाबरी मस्जिद बनाना चाहते होते। लेकिन, इतने भर के लिए राजनाथ सिंह की बात को झूठ कहना, सही है क्या? असल में ऐसे मामलों को झूठ और सच के खानों में बांटकर देखना ही गलत है। और इस तरह की भौतिकवादी दलीलों के पीछे भागना तो और भी गलत है कि सरदार ने अपने जीते-जी तो किसी को बाबरी मस्जिद गिराने नहीं दी थी। और जब मस्जिद साबुत खड़ी थी, तो नेहरू जी सरकारी पैसे से उसे बनवाने की सोचते भी तो कैसे? सरदार पटेल 1950 में परलोक सिधार गए और नेहरू जी 1964 में। उनका सच उनके साथ चला गया। अब हम क्या 1950 के सच पर ही अटके रहेंगे या मणिबेन ने जो सच बताया उस पर? पचहत्तर साल में गंगा-जमुना में बहुत पानी बह चुका है। इस दौरान बहुत कुछ हो चुका है। आडवाणी की रथयात्रा भी हो चुकी है और मस्जिद को भीड़ जुटाकर गिराया भी चुका है। अदालत के फैसले के नाम पर, मंदिर वहीं बनाया भी जा चुका है और अभी पिछले ही दिनों, मंदिर पर मोदी द्वारा झंडा भी फहराया जा चुका है। 1950 का सच अलग था, 2025 का सच अलग है! 1950 में जहां मस्जिद थी, 2025 में वहीं मंदिर है, इससे अलग और नया सच क्या होगा? और जब सब नया है, तो नेहरू और पटेल के बीच बहस का सच, नया और मणिबेन की डायरी वाले सच से डिफरेंट क्यों नहीं हो सकता? तब का सच जो था सो था, आज का सच यही है कि जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे और सरदार पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोका था! और अगर वाकई विरोधी इसे झूठ मानते हैं तो एफीडेविट देकर कहें कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद, जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से मस्जिद दोबारा नहीं बनवाते या सरदार पटेल उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकते! राजनाथ सिंह ने जो कहा है, उसमें झूठ नहीं है, बस अपनी कल्पना के सहारे उन्होंने सच की जरा सी अपडेटिंग की है; सच को अमृतकालीकरण किया है। राजनाथ सिंह सच का अमृतकालीकरण नहीं करते थे, तो 6 दिसंबर को शौर्य दिवस कैसे मनाते? राजस्थान के शिक्षा मंत्री को 2025 में भी स्कूलों में बच्चों से शौर्य दिवस नहीं मनवाने दिया, तो इसका मतलब यह थोड़े ही है कि राजनाथ सिंह भी शौर्य दिवस नहीं मनाएंगे। आखिर, अपने ध्वजारोहण वाले भाषण में 6 दिसंबर के शौर्य का यशोगान तो मोदी जी ने भी किया होगा। राजनाथ सिंह ने तो उनका अनुसरण ही किया है, बस शौर्य दिवस में जरा सा नेहरू जी के मस्जिद-समर्थन का तड़का लगाया है। देखा-देखा, विपक्ष वालों का नकलचीपन देखा! कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह को देश के पहले प्रधानमंत्री, नेहरू जी के बारे में झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी चाहिए। अब बताइए, अपने विरोधियों से माफी मांगने की मांग करना, भगवा पार्टी की खास निशानी है या नहीं? विपक्ष वाले मुंह बाद में खोलते हैं, मामला चाहे अडानी हो या चुनाव आयोग का हो, आरएसएस का हो या सावरकर का हो और अगर मोदी का हो तब तो कहना ही क्या, कोई संबित पात्रा या कोई किरण रिजिजू या कोई रविशंकर प्रसाद, राहुल गांधी माफी मांगो की मांग करने पहले सामने आ जाता है। विपक्ष वाले इतनी बेशर्मी से कैसे भगवा पार्टी का ट्रेड मार्क चुरा सकते हैं और भगवा पार्टी की मांग का तीर, उसी पर चला सकते हैं? माना कि भगवा पार्टी वालों ने विरोधियों से माफी की मांग करने के दांव का पेटेंट अपने नाम नहीं कराया था। कराना चाहिए था। अपने इस नायाब आविष्कार को उन्हें पेटेंट कराना चाहिए था। आपका दांव कोई दूसरा आप पर ही नहीं आजमा सके, इसी के लिए तो पेटेंट कराना जरूरी था। लेकिन, क्या पेटेंट ही सब कुछ है? नैतिकता कोई चीज नहीं है? सारी दुनिया को पता है कि विरोधियों से माफी मांगने की मांग करना, किस का आविष्कार है। सब जानते हैं कि भगवा पार्टी वाले अपने इस आविष्कार का किस तरह रोज-रोज इस्तेमाल करते रहे हैं।

# हवाई हड़ताल और यात्री

**भारत** में विमानन उद्योग निजी क्षेत्र से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र तक में सैर करता रहा है मगर इससे पहले कभी ऐसी अफरा- तफरी का माहौल नहीं बना जैसा कि आजकल बना हुआ है। देश के सभी हवाई अड्डों पर यात्रियों की भीड़ है जो अपने गन्तव्य तक जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मगर देश की निजी एयर लाइनों में से सबसे प्रमुख इंडिगो एयर लाइन ने हड़ताल कर रखी है जिसकी वजह से दूसरी एयर लाइनें मनमाना किराया वसूल रही हैं और हद यह हो गई है कि दिल्ली से मुम्बई तक की हवाई यात्रा का टिकट 60 हजार रुपए तक हो गया है। वास्तव में यह अराजकता का वातावरण है जिसकी तरफ भारत सरकार के नागरिक विमानन उड्डयन मन्त्रालय ने अब ध्यान दिया है। पिछले लगभग चार दिन से ऐसा ही माहौल बना हुआ है। देश में अब सरकार के हाथ में एक भी एयर लाइन नहीं है। घरेलू उड़ानों से लेकर विदेशी उड़ानों तक का कामकाज निजी एयर लाइनों के हाथ में है। इनमें से इंडिगो एयर लाइन के पास घरेलू उड़ानों का 65 प्रतिशत कारोबार है जबकि एयर इंडिया व अन्य विमानन कम्पनियों के पास शेष बाजार है। एयर इंडिया मुख्यतः विदेशी उड़ानों का कारोबार करती है। एयर इंडिया का निजीकरण हुए अभी कुछ वर्ष ही बीते हैं। इससे पहले यह सरकार के हाथ में थी मगर इसे टाटा समूह को बेच दिया गया। बाजार मूलक खुली अर्थव्यवस्था का नियम होता है कि इसमें उपभोक्ता मूलक बाजार संस्कृति को महत्व दिया जाता है अर्थात विभिन्न कम्पनियों के बीच जब प्रतियोगिता का माहौल बनता है तो उपभोक्ता को उत्पाद या सेवा प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध होती है। मगर बाजार पर यदि किसी एक कम्पनी का ही अधिपत्य हो जाता है तो वह बेखौफ होकर उपभोक्ताओं से मनमाना मूल्य वसूल करती है। भारत के विमानन क्षेत्र में आजकल यही हो रहा है और भारत का प्रतियोगिता आयोग (कम्पटीशन कमीशन) सोया हुआ पड़ा है। 1991 से पहले जब भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था में चल रहा था तो भी देश में एकाधिकार निरोधक आयोग( एमआरटीपीसी) था जो लगातार चौकन्ना होकर किसी एक कम्पनी को बाजार पर एकाधिकार करने से रोकता था लेकिन खुली बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता आयोग द्वारा कलम हिलाने की शायद ही कोई घटना प्रकाश में आई हो जबकि बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में बाजार पर एकाधिकार जमाने की संभावनाएं भी सर्वाधिक बनी रहती हैं। केन्द्र सरकार का ध्यान अब इस तरफ गया लगता है तभी उसने घरेलू उड़ानों का किराया नियत करने की तरफ जरूरी कदम उठाया है। अब 500 कि.मी. तक की हवाई दूरी तक के लिए अधिकतम किराया 7500 रुपए होगा जबकि 500 से 1000 किमी. दूरी के लिए 12 हजार होगा और एक हजार से डेढ़ हजार कि.मी. दूरी तक के लिए यह 15 हजार रुपए होगा। इससे ऊपर दूरी तक के लिए यह 18 हजार रुपए होगा। भारत में दिल्ली से चेन्नई की दूरी डेढ़ हजार किमी से ऊपर है। सवाल यह है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी जिसकी वजह से सरकार को हरकत में आना पड़ा? इसका कारण इंडिगो एयर लाइन में पायलटों की हड़ताल थी। पायलटों ने यह हड़ताल अपनी सेवा शर्तों में बदलाव की वजह से की। इसकी वजह से एयर लाइन ने अपनी उड़ानों को रद्द करने का नया रिकार्ड बना डाला और इनकी संख्या हजारों में पहुंच गई। जाहिर है इसकी वजह से पूरे देश के हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी बननी ही थी और यात्रियों को परेशानी होनी ही थी। अब जाकर सरकार ने इंडिगो एयर लाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जवाब तलबी की है और पूछा है कि उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई क्यों न की जाये। कारण बताओ नोटिस जारी करके सरकार के उड्डयन मन्त्रालय ने अपनी जान बचाने की कोशिश ही की है जिससे नागरिकों का गुस्सा उस पर न उतर सके। मगर लोकतन्त्र में अन्तिम जिम्मेदारी सरकार की ही होती है जिससे वह अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। वर्तमान में उड्डयन मन्त्रालय का कार्यभार तेलगूदेशम पार्टी के श्री राम मोहन नायडू के पास है। यह पार्टी केन्द्र की मोदी सरकार में शामिल है परन्तु लोकतन्त्र में सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है जिससे सत्ता में बैठी कोई भी पार्टी अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। अतः केन्द्र सरकार को ही सामूहिक तरीके से यह सोचना होगा कि निजी विमानन कम्पनियों द्वारा किसी भी तरीके से उपभोक्ताओं या यात्रियों का शोषण न हो सके। इस बहाने सरकार यह भी जरूर सोचे कि देश की सभी विमानन कम्पनियों का निजीकरण करके कहीं उसमें कोई चूक तो नहीं हो गई है। वास्तव में पिछली मनमोहन सरकार के दौरान ही एयर लाइनों के निजीकरण की आधारशिला रख दी गई थी। उस समय नागर विमानन मन्त्री राष्ट्रवादी कांग्रेस के श्री पटेल थे। उन्होंने एयर इंडिया व इंडियन एयर लाइनों का पहले विलीनीकरण किया और बाद में विलीनीकृत एयर इंडिया को घाटे में लाकर खड़ा कर दिया। श्री पटेल के कार्यकाल के दौरान लाभप्रद घरेलू व विदेशी हवाई रूट निजी कम्पनियों को आवंटित किये गये जिससे सरकारी एयर लाइन का घाटा बढ़ता ही गया और मोदी सरकार में स्थिति यह आ गई कि केवल दो निजी कम्पनियों का पूरे हवाई बाजार पर एकाधिकार हो गया। अतः इस स्थिति को भी बदलने की जरूरत है।

## अब गंग नहर की शताब्दी पर उठे विवाद

**राजस्थान** की ऐतिहासिक गंग नहर अपने निर्माण के 100 वर्ष पूरे कर रही है। पंजाब के ऐतिहासिक शहर फिरोजपुर से सतलुज नदी का पानी लेकर राजस्थान के रेतीले इलाकों में हरियाली लाने के लिए बनी यह नहर भारत-पाक सीमा के करीब है और यह फिरोजपुर, फाजिल्का और जिला मुक्तसर से होती हुई जिला गंगानगर व जिला हनुमानगढ़ के क्षेत्रों तक जल ले जाती है। ठीक 100 वर्ष पूर्व दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ था। इसका पहली बार प्रयोग अक्तूबर 1925 में आरंभ हुआ। इसके निर्माण की पहलकदमी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने की थी। इस नहर के निर्माण की शताब्दी पूर्ण होने पर एक विशेष समारोह के आयोजन की योजना थी, मगर अब इस पर भी विवाद मचा हुआ है। पंजाब का आरोप है कि उसके तीन-तीन जिलों से होकर गुजरने वाली इस नहर का मूल स्रोत भी पंजाब की सतलुज नदी है, मगर पंजाब को इस नहर का एक बूंद पानी भी नहीं मिल पाता। अब इस पर नया हंगामा आरंभ हो गया है। चलिए, इस नहर की शताब्दी के अवसर पर इसके अतीत पर नजर दौड़ा लें। वर्ष 1899-1900 में देश के कई भागों में अकाल पड़ा था। उन दिनों बीकानेर-रियासत सबसे अधिक प्रभावित हुई थी। पानी की बूंदों के लिए इंसान भी तरसते थे और खेत भी। परिंदे भी दम तोड़ने लगे थे और पौधे भी सूख चले थे। उस समय बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब के तत्कालीन चीफ इंजीनियर ए.डब्ल्यू. ई. स्टैनले और एक अन्य उच्चाधिकारी आर.जी. कैनेडी की मदद से इस नहर की योजना तैयार कराई थी। मगर तत्कालीन मुस्लिम स्टेट बहावलपुर ने इसका विरोध किया था। बाद में वायसराय लार्ड कर्जन के दखल से 4 सितम्बर, 1920 को एक समझौता हुआ था। नहर का नींव पत्थर 5 दिसम्बर, 1925 को रखा गया, मगर इस नहर को जल के लिए लार्ड कर्जन ने ही दो वर्ष बाद 1925 में खोला था। भारत-पाक विभाजन के समय सर सिरिल रैडक्लिफ शुरूआती दौर में फिरोजपुर और जीरा तहसील को पाकिस्तान में मिलाने लगे थे। अगर ऐसा हो जाता तो गंग कैनाल का सारा पानी पाकिस्तान को मिल जाता। उन दिनों सरदार के.एम. पनिक्कर, बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने लार्ड माउंटबेटन को चेतावनी दी थी कि यदि ऐसा हुआ तो बीकानेर रियासत के पास पाकिस्तान के विलय के इलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। जवाहर लाल नेहरू ने भी इसी विषय पर वायसराय को एक पत्र लिखा था। आखिर रैडक्लिफ को अपनी भूल का अहसास हो गया। उसने पूरा जिला फिरोजपुर ही भारत के हिस्से में डाल दिया। बहरहाल, अब विवाद एक नया मोड़ ले रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, जो कि राजस्थान के प्रमुख नेता भी हैं, ने फिरोजपुर हैड वर्क्स पर जाकर उस स्थान पर एक समारोह की योजना बनाई थी, जहां से इस नहर का उद्गम होता है। मगर इसी बात पर पंजाब की सिख राजनीति में नया बवाल मच गया। सत्तापक्ष 'आप' ने भी इस पर अपनी उग्र आपत्ति जताई थी। श्री अर्जुन मेघवाल ने स्पष्ट कर दिया कि उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि फिरोजपुर जाकर एक समारोह का आयोजन करें ताकि पंजाब के प्रति आभार जताया जा सके। बाद में पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ और भाजपा नेता गुरमीत सोढ़ी को भी अपने-अपने बयान जारी करने पड़े और मेघवाल के इस कार्यक्रम से दूरी बनाने की घोषणा करनी पड़ी।

# संचार साथी, नाम की राजनीति और बंगाल की चुनौतियां

**पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता शरद पवार की संसदीय पारी समाप्त होती लग रही है। शरद पवार ने लोकसभा का चुनाव लड़ना बंद किया तो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बारामती सीट सौंप दी। उसके बाद से शरद पवार राज्यसभा में हैं। इस बार उनकी पार्टी सिर्फ 10 विधानसभा सीट जीत पाई है। इसीलिए सवाल है कि वे कैसे राज्यसभा जाएंगे? महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को कुल 51 सीटें मिली हैं। इनमें उद्धव ठाकरे की शिव सेना के 20, कांग्रेस के 16 और शरद पवार की पार्टी के 10 विधायक हैं। इनकी मदद से राज्यसभा की एक सीट जीती जा सकती है। अगर तीनों पार्टियां चाहे तो शरद पवार को फिर से राज्यसभा भेज सकती हैं। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा की लंबी पारी के भी खत्म होने का समय आ गया है। देवगौड़ा की उम्र 90 साल से ज्यादा है और उन्होंने अपनी लोकसभा सीट अपने पोते को सौंप दी। अब उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और सिर्फ 19 सीटें जीती उनकी पार्टी अपने दम पर राज्यसभा की सीट नहीं जीत सकती है। राज्य में अगले साल चार सीटें खाली हो रही हैं। इनमें से एक सीट भाजपा को मिल सकती है। अगर भाजपा उदारता दिखाए तो ही देवगौड़ा राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन वह देवगौड़ा के लिए यह सीट छोड़ देगी, इसमें संदेह है। वैसे देवगौड़ा की उम्र को देखते हुए यह भी हो सकता है कि उन्हें आराम दे दिया जाए।**

अनिल जैन

केंद्र सरकार ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। हालांकि यह यू टर्न किस्तों में आया लेकिन आ गया। दूरसंचार विभाग ने एक आदेश जारी करके कहा था कि अब अगले 90 दिन में हर स्मार्ट फोन में संचार साथी' ऐप प्री इंस्टाल होगा। स्मार्ट फोन बनाने वाली कंपनियों को इसका निर्देश दे दिया गया था और डिजिटल टीवी चैनलों के जरिये जनता को इसके फायदे समझाए जाने लगे थे। लेकिन जब इसका विरोध तेज हुआ और विपक्ष के साथ-साथ सिविल सोसायटी और सरकार के इकोसिस्टम के लोगों ने भी विरोध शुरू किया तो सरकार की ओर से कहा गया कि यह ऐप प्री इंस्टाल तो होगा लेकिन अगर यूजर चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हैं। जब इस पर भी विरोध जारी रहा तो अगले दिन यानी बुधवार को कहा गया कि यह ऐप प्री इंस्टाल नहीं होगा। यह केंद्र सरकार का नया यू टर्न है। इससे पहले आरोग्य सेतु' ऐप को भी सरकार ने अनिवार्य बनाने की पहल की थी और विरोध होने पर उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। पिछले ही साल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल पर भी सरकार पीछे हटी और ड्राफ्ट वापस लिया। उससे पहले 2021 में भारी विरोध के बाद तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया। उससे भी पहले शुरुआत 2015 में ही हुई थी, जब केंद्र सरकार ने विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक वापस लिया था।

**राजभवन का नाम लोकभवन करने से क्या होगा?**

पिछले एक दशक के दौरान कई शहरों, गांवों, कस्बों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, संस्थाओं, इमारतों और सड़कों के नाम बदले गए हैं। ऐसा करना भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों का खास शौक है, इसलिए नाम बदलने का सिलसिला अभी भी जारी है। दिल्ली में राजपथ का नया नाम कर्तव्य मार्ग, केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन, रेसकोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग किया गया है, उसी तर्ज पर अब प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ और राज्यों की की राजधानियों में स्थित राजभवनों का नाम लोक भवन कर दिया गया है। सवाल है कि नाम बदलने से होता क्या है? अब राज्यपालों के निवास राजभवन को ही लें। देश में पिछले कुछ सालों के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद अगर कोई संवैधानिक पद सबसे ज्यादा बदनाम हुआ है तो वह है राज्यपाल का पद। वैसे यही सबसे ज्यादा बेमतलब का पद भी है। इसीलिए भारी भरकम खर्च वाले इस संवैधानिक पद की उपयोगिता पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। सवाल उठाने का मौका भी कई राज्यपाल खुद ही अपनी अटपटी और असंवैधानिक हरकतों से उपलब्ध कराते हैं। ऐसे ज्यादातर राज्यपाल उन राज्यों के होते हैं जहां केंद्र में सत्तारूढ़ दल के विरोधी दल की सरकारें होती हैं। पिछले कुछ सालों से तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में राजभवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तब्दील हो चुके हैं और वहां के राज्यपाल विपक्ष के नेता की भूमिका में काम कर रहे हैं; जिससे आए दिन विवाद होते रहते हैं। इसलिए जरूरत राज्यपालों का चाल-चलन बदलने की है; न कि राजभवनों का नाम बदलने की।

**दिल्ली में भाजपा और आप को सबक**

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को सबक मिला है। चुनाव ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की 12 सीटों के नतीजों से दिल्ली के लोगों ने एक राय प्रकट की है। दिल्ली के लोगों ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। भाजपा पहले से जीती हुई नौ में से दो सीटों पर चुनाव हार गई है। एक सीट पर उसको आम आदमी पार्टी ने हराया तो दूसरी सीट पर कांग्रेस ने हराया। हालांकि भाजपा के नेता संतोष कर रहे हैं कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है लेकिन इससे दो सीटें हारने की भरपाई नहीं हो सकती। लग रहा है कि महिला सम्मान योजना के पैसे नहीं दिए जाने, मोहल्ला क्लीनिक से लोगों की छंटनी, बस मार्शल को स्थायी नहीं करने और प्रदूषण के मामले ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस ने संगम विहार की सीट जीती है। यह मामूली बात नहीं है। यह आम आदमी पार्टी के लिए झटका है। वैसे यह सीट कांग्रेस ने भाजपा से छीनी है लेकिन भाजपा से नाराज लोग आम आदमी पार्टी की ओर न जाकर कांग्रेस के साथ गए है यह आप के लिए झटका है। उसे दूसरा झटका चांदनी महल सीट पर लगा है, जहां उसकी पार्टी छोड़ने वाले शुएब इकबाल ने अपनी रिश्तेदार को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की टिकट पर चुनाव जीता दिया। वहां दूसरे स्थान पर भाजपा रही। इसका अर्थ है कि मुसलमानों के बीच भी आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत सकारात्मक माहौल नहीं है।

विवादों से घिरे चुनाव आयोग के सामने पश्चिम बंगाल में हर दिन नई-नई चुनौती सामने आ रही है। सरकार की ओर से असहयोग, अधिकारियों का असहयोग, बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ का संगठन बना कर विरोध प्रदर्शन आदि चुनौतियों से तो चुनाव आयोग निबट ही रहा था कि इस बीच उसके सामने नई चुनौती आ गई है। हजारों मतदान केंद्रों से सौ फीसदी मतगणना प्रपत्र जमा हो रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि 22 सौ से ज्यादा मतदान केंद्रों पर सौ फीसदी मतदाता प्रपत्र भर कर वापस लौटे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 750 से ज्यादा बूथ अकेले उत्तरी 24 परगना के हैं। इसके अलावा नादिया, दक्षिण 24 परगना, मिदनापुर, माल्दा आदि के भी बूथ हैं। चुनाव आयोग ने इस पर जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि पिछले 22 साल में किसी इलाके में एक भी मतदाता की मौत नहीं हुई हो या कोई स्थायी तौर पर शिफ्ट नहीं हुआ या कोई अपने घर से गैरहाजिर नहीं हो या किसी का नाम एक से ज्यादा मतदान केंद्र पर न हो। इन चार श्रेणियों के कारण हर मतदान केंद्र पर सात-आठ फीसदी तक मतगणना प्रपत्र कम भरे जा रहे हैं। लेकिन 2,208 मतदान केंद्रों से सौ फीसदी फॉर्म लौट आए हैं। हो सकता है कि कुछ और जगहों से ऐसा देखने को मिले। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव आयोग को सबक सिखा रही है।

**पवार और देवगौड़ा की पारी समाप्ति की ओर**

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता शरद पवार की संसदीय पारी समाप्त होती लग रही है। शरद पवार ने लोकसभा का चुनाव लड़ना बंद किया तो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बारामती सीट सौंप दी। उसके बाद से शरद पवार राज्यसभा में हैं। इस बार उनकी पार्टी सिर्फ 10 विधानसभा सीट जीत पाई है। इसीलिए सवाल है कि वे कैसे राज्यसभा जाएंगे? महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को कुल 51 सीटें मिली हैं। इनमें उद्धव ठाकरे की शिव सेना के 20, कांग्रेस के 16 और शरद पवार की पार्टी के 10 विधायक हैं। इनकी मदद से राज्यसभा की एक सीट जीती जा सकती है। अगर तीनों पार्टियां चाहे तो शरद पवार को फिर से राज्यसभा भेज सकती हैं। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा की लंबी पारी के भी खत्म होने का समय आ गया है। देवगौड़ा की उम्र 90 साल से ज्यादा है और उन्होंने अपनी लोकसभा सीट अपने पोते को सौंप दी। अब उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और सिर्फ 19 सीटें जीती उनकी पार्टी अपने दम पर राज्यसभा की सीट नहीं जीत सकती है। राज्य में अगले साल चार सीटें खाली हो रही हैं। इनमें से एक सीट भाजपा को मिल सकती है। अगर भाजपा उदारता दिखाए तो ही देवगौड़ा राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन वह देवगौड़ा के लिए यह सीट छोड़ देगी, इसमें संदेह है। वैसे देवगौड़ा की उम्र को देखते हुए यह भी हो सकता है कि उन्हें आराम दे दिया जाए।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कदम ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पीसीसी एक्स, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया संपादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/08862)

# एसआईआर कार्य में बर्दाश्त नहीं की जायेगी लापरवाही: मुख्यमंत्री

मुरादाबाद।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को मुरादाबाद पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि एसआईआर में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता टोलियां बनाकर घर-घर जनसंपर्क करें। फर्जी वोटरों के नाम हटवाएं और सही वोटरों को जोड़ने का काम करें। योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के सर्किट हाउस में सोमवार दोपहर एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंडल के जिला प्रभारियों और जिलाध्यक्षों ने विकास की योजनाओं और एसआईआर की प्रगति के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि

## मुरादाबाद पहुंचकर की एसआईआर कार्य की समीक्षा

आम जनता के लिए एसआईआर गंभीर मुद्दा है। पार्टी के बीएलओ -1, बीएलओ -2 का सहयोग करें। बांग्लादेशी घुसपैठिये किसी कीमत पर वोटर नहीं बनने चाहिए। पार्टी के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी लापरवाही न बरतें। मतदाता सूची 2003 के अनुसार मृत और फर्जी वोटरों के नाम कटवाएं। इसके लिए पार्टी के पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं के साथ टोली बनाकर घर घर जनसंपर्क करना होगा। इसके

साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लें। विकास की योजनाएं कहां तक पहुंची है। अगले साल पंचायत चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव आएंगे। इस कारण पार्टी की तैयारी मजबूत रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कुछ जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र के बूथ पूछे तो करीब करीब बताने पर मुख्यमंत्री ने तो टूक कहा कि सीधे तौर पर बूथ संख्या बताइए। फिर मुख्यमंत्री ने सभी से कहा कि सभी एसआईआर के काम में लग जाइए। एक-एक मतदाता का वोट अनिवार्य रूप से बने। जो सही वोट है किसी भी दशा में रहने ना पाए और गलत वोट बनने ना पाए। जनप्रतिनिधि यह अनिवार्य रूप से तय कर लें। यह भी कहा कि चुनाव में अभी से जुटने का यह सबसे महत्वपूर्ण वक्त है। एक-एक मतदाता का जब वोट आप सुनिश्चित करेंगे। एक-एक बूथ, एक-एक मतदाता तक पहुंचेंगे तो आपकी चुनाव की तैयारी खुद-ब-खुद पूरी होगी। बैठक में माध्यमिक शिक्षा मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) गुलाब देवी, रा'य मंत्री बलदेव सिंह औलख, विधान परिषद सदस्य डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त, डॉ. हरि सिंह ढिल्ले, राम गोपाल उर्फ गोपाल अन्जान, भाजपा विधायक रितेश कुमार गुप्ता, ठाकुर रागवीर सिंह, आकाश सक्सेना, कुँवर सुशांत सिंह, सुश्री मौसम चौधरी, अशोक कुमार राणा, ओम कुमार, राजीव तराए, महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, महापौर विनोद अग्रवाल, मण्डल ने पांचों जनपदों के भाजपा जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. केके मिश्रा, हरिओम शर्मा प्रदेश महामंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिला पंचायत अध्याय डॉ. शैफाली सिंह चौहान, गिरीश भंडूला समेत भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। मण्डलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह, डीआईजी मुनिराज, जिलाधिकारी अनुज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अन्तिल आदि ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

# वोट चोर, गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी में जुटे कांग्रेसी

मुरादाबाद।

महानगर कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक चौमुखापुल स्थित महानगर कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमे दिल्ली के रामलीला मैदान मे आयोजित होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी को लेकर पार्षदगणो, महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों,ब्लॉक, मण्डल, वार्ड अध्यक्ष गणों से विचार विमर्श किया गया। महानगर अध्यक्ष जुनैद इकराम ने अपने सम्बोधन मे सभी कांग्रेस जनो से महारैली मे बढ़-चढ़कर भाग लेने एंव रैली को सफल बनाने का आह्वान किया और महानगर से 1000 लोगो को रैली मे ले जाने का लक्ष्य तय किया। बैठक मे अजय सारस्वत सोनी,फहीम मिर्जा,असद मौलाई,अनुभव महरोत्रा,नजाकत ठेकेदार,मुशाहिद चौधरी,वॉर इंचार्ज मौ0शादान, पार्षद कमर सलीम पार्षद नदीम उद्दीन कातिब,पार्षद नदीम अंसारी,पार्षद मौअ'जम,पार्षद

## दिल्ली रामलीला ग्राउंड में होगी महारैली

मौअ'जम अली,पार्षद अफसर अंसारी,पार्षद आरेफीन मदनी,पार्षद रेहान,पार्षद फहीम एडवोकेट,पार्षद नईम पप्पू,पार्षद मौज्जुनैद,पार्षद नाजिम,पार्षद सद्दाम हुसैन,पार्षद प्रतिनिधि काशिफ,पार्षद राशिद अली,पार्षद परवेज उर्फ नन्ना,पार्षद भारतीय परवेज इस्लाम,पार्षद इफ्तिखार, जईम चौधरी,कबीर अहमद, जमीर अहमद,महफूज उर्फ राजा, युनूस सैफी,वाहिद सैफी,सोनी सैफी,शरीफ घोसी,फहीम टीटू,जावेद नबी खान,शकील सिद्दीकी,दानिश कुरैशी,मौज्अनस,अहमद अयाज,विजय सिंह,अनुराग शर्मा,रईस उल कलाम,सुफियान खान,शन्नू पठान,अफसर खान,बन्ने पहलवान,रफीक मसूदी,शरीफ घोसी, राजीव कुमार शर्मा,समीर खान,नाजिम परवेज,आमिर रहमान,नदीम उर्फ गुड्डन,अनमोल गुप्ता,आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे।

# सीता रसोई ने किया निःशुल्क भोजन का वितरण

मुरादाबाद। सीता रसोई ट्रस्ट के अध्यक्ष उदयभान सिंह ने बताया कि हमारी संस्था के द्वारा नियमित और निशुल्क भोजन वितरण किया जाता है जिसमें चलते-फिरते राहगीर, रेहड़ी लगाने, वाले पटरी वाले, जरूरतमंद दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को सीता रसोई निशुल्क और भरपेट भोजन करवाती है। उन्होंने यह भी बताया कि संस्था किसी भी तरह का कोई सरकारी सहयोग नहीं लेती है यह सेवा केवल सामाजिक सहयोग से संचालित हो रही है जिसमें सीता रसोई के मासिक सदस्य दैनिक सदस्य आजीवन सदस्य तथा संरक्षक मंडल एवं बोर्ड मेंबर के द्वारा एक निश्चित राशि प्रतिमाह जमा की जाती है जिससे कि यह भोजन की व्यवस्था संचालित की जाती है और समाज के लोग अपने परिवार में किसी भी प्रिय जनों के विशेष अवसर पर जैसे की जन्मदिवस वैवाहिक वर्षगांठ और किसी प्रियजन की पुण्यतिथि पर सीता रसोई पर आकर के निशुल्क भोजन करवाते हैं । आज की भोजन की व्यवस्था में सहयोग श्रीमती मंजू वर्मा जी एवं उनके समस्त परिवार के द्वारा भोजन वितरण करवाया गया सीता रसोई के संरक्षक हिरदेश कुमार सिंह वित्त सचिव सुनील कुमार शर्मा,में सचिव विवेक पांडे सह सचिव दीपक गुप्ता सह सचिव राकेश कुमार वर्मा वरिष्ठ सदस्य मनोज सिन्हा पवन उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश वार्ष्णेय , विजय वर्मा , एवं संरक्षक मंडल के साथ-साथ सभी सदस्य सीता रसोई पर उपस्थित होकर भोजन वितरण में सहायता करते हैं।

# गोष्ठी में डॉ. अम्बेडकर के व्यक्तित्व पर डाली रोशनी

मुरादाबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की मुरादाबाद महानगर इकाई ने हिंदू कॉलेज में भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शहर के शिक्षाविदों, एबीवीपी पदाधिकारियों और कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गोष्ठी का शुभारंभ डॉ. अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कॉलेज के प्रॉक्टर जी.के. शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने डॉ. अंबेडकर के जीवन भर के सामाजिक समानता, शिक्षा और न्याय के संघर्ष पर प्रकाश डाला। शर्मा ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण में उनका योगदान विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। कार्यक्रम में जितेंद्र, संजीव, चंद्रजीत और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर सहमंत्री छविनाथ अरोरा भी उपस्थित रहे। अन्य वक्ताओं ने डॉ. अंबेडकर के कमजोर और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान में निहित अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी प्रत्येक छात्र तक पहुंचनी चाहिए, ताकि देश एक सशक्त और समरस भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और डॉ. अंबेडकर के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। वक्ताओं के संबोधन के दौरान उपस्थित युवा वर्ग ने तालियों की गड़गड़ाहट से अपना उत्साह व्यक्त किया। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों द्वारा किया गया, जिसके बाद राष्ट्रगान के साथ गोष्ठी का समापन हुआ।

# टीएमयू नर्सिंग ब्रह्मोत्सव में अग्नि ओवरऑल चैंपियन

मुरादाबाद।

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर कॉलेज ऑफ नर्सिंग और तीर्थंकर पार्श्वनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अमरोहा के वार्षिक खेल और सांस्कृतिक महोत्सव- ब्रह्मोत्सव-2025 में अग्नि टीम ओवर ऑल चैंपियन रही। ओवर ऑल चैंपियनशिप का खिताब स्पोर्ट्स और क्लचरल इवेंट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर दिया गया। अग्नि टीम को डीन एकेडमिक्स प्रो. मंजुला जैन ने विजेता ट्राफी देकर सम्मानित किया। खेल प्रतियोगिताओं में वायु टीम ने सर्वाधिक 09 गोल्ड, 07 सिल्वर और 05 ब्रॉन्ज मेडल, नीर टीम ने 08 गोल्ड, 06 सिल्वर और 07 ब्रॉन्ज, अग्नि टीम ने 06 गोल्ड, 07 सिल्वर और 07 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए। इस मौके पर नर्सिंग

## ब्रह्मोत्सव-2025 अविस्मरणीय यादों के संग विदा

कॉलेज की डीन प्रो. एसपी सुभाषिनी, नर्सिंग कॉलेज, मुरादाबाद की प्रिंसिपल डॉ. जसलीन एम., नर्सिंग कॉलेज, अमरोहा की प्रिंसिपल प्रो. श्योली सेन, वाइस प्रिंसिपल प्रो. राम निवास सिंह आदि मौजूद रहे। दूसरी ओर इससे पूर्व टीएमयू के रिद्धि-सिद्धि भवन में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्जवलन के संग सांस्कृतिक प्रोग्राम्स का शुभारम्भ हुआ। इस सुअवसर पर टीएमयू हॉस्पिटल में मनोचिकित्सा विभाग की प्रो. प्रेरणा गुप्ता, सीटीएलडी के उपनिदेशक डॉ. दिलीप दत्त वार्ष्णेय आदि की उल्लेखनीय मौजूदगी रही । सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में टीम अग्नि का भी जलवा रहा। फेस पेंटिंग में अग्नि के अमन कुमार विजेता रहे, जबकि टीम अग्नि की नगी थियानहोई दूसरे स्थान पर रही। पॉट पेंटिंग में टीम आकाश की सोनिया रानी प्रथम और टीम अग्नि की निधि रानी द्वितीय स्थान पर रही। रंगोली प्रतियोगिता में टीम वायु की अशिया, हिमांशी और शिवानी संयुक्त रूप से विजेता रही, जबकि टीम अग्नि की वंशिका, निधि, नूर और प्रज्ञा सेकेंड स्थान पर रहीं। मेहंदी प्रतियोगिता में टीम वायु के सचिन विजेता रही। टीम वायु के सफा तारिक दूसरे, जबकि टीम अग्नि की कामना तीसरे स्थान पर रही। कार्ड मेंकिंग में टीम अग्नि के नगी थियानहोई, प्रज्ञा शर्मा और सोनाक्षी क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे। सोलो डांस में टीम अग्नि की केंजल अव्वल रही, जबकि उत्तरेक्शा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। डुएट डांस में वायु के शिवम एंड सिमरन विजेता रहे और अग्नि के उदित एंड जेस्मिन सेकेंड स्थान पर रहे। सोलो सिंगिंग में आकाश टीम के आयुष प्रथम, जबकि नीर टीम के अंकुर द्वितीय स्थान पर रहे। ग्रुप डांस में अग्नि टीम के किरणजीत एंड समूह विजेता रहा। आकाश टीम की रिया एंड समूह ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। संचालन मिस पवित्रा और वैष्णवी ने किया। कार्यक्रम के दौरान स्पोर्ट्स कोर्डिनेटर्स- श्री सतीश प्रजापति, श्री रितिक कुमार, श्री विनय लाल, श्रीमती पूजा झा के साथ साथ प्रो. जितेन्द्र सिंह, डॉ. रामकुमार गर्ग, प्रो. अनुषी सिंह, डॉ. सुमन वशिष्ठ, प्रो. विजी मोल, श्री वेदमूर्ति, श्री गौरव कुमार, प्रो. वरुण तोषनीवाल, श्री मुकुल सिंह, मिस शालू उपाध्याय आदि मौजूद रहे।

# अखिल भारतीय मुस्लिम बंजारा एकता समाज को मिला नया नेतृत्व-गुलाम मुस्तफा बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाज में खुशी की लहर!

नई दिल्ली ( साहिल गौड़ ) अखिल भारतीय मुस्लिम बंजारा एकता समाज (AIMBES) के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक परिवर्तन आया है, जिसने पूरे बंजारा समाज में उत्साह और आशा की नई लहर पैदा कर दी है। एक लोकतांत्रिक और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया के माध्यम से, गुलाम मुस्तफा को समाज का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। उनकी भारी जीत को बंजारा समाज के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

समाज ने मुस्तफा के विजन पर जताया भरोसा

राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन गुलाम मुस्तफा ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर अपनी नेतृत्व क्षमता और समाज में अपनी गहरी पकड़ को साबित कर दिया। मतदान के परिणामों ने उनके प्रति समाज के विश्वास को मजबूती से दर्शाया।

गुलाम मुस्तफा को प्राप्त 42 मतों की संख्या उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी (22 मत) और निवर्तमान अध्यक्ष (8 मत) की तुलना में कहीं अधिक है, जो यह स्पष्ट करता है कि समाज एक मजबूत और परिवर्तनकारी नेतृत्व की तलाश में था। चुनाव परिणाम घोषित होते ही पूरे देश में मुस्लिम बंजारा एकता समाज के सदस्यों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया।

खुशी का माहौल और नई उम्मीदें

नवनियुक्त अध्यक्ष के चुनाव के बाद, अखिल भारतीय मुस्लिम बंजारा एकता समाज के सदस्यों में अभूतपूर्व खुशी का माहौल है। समाज के वरिष्ठ सदस्यों और युवाओं ने इस चुनाव को लोकतंत्र की जीत और गुमशुदा विकास की वापसी करार दिया है।

यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि हमारे समाज की दबी हुई आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। गुलाम मुस्तफा में हम एक ऐसे नेता को देखते है जो हमारे बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, और बड़ों के लिए सम्मान और हमारे समाज के लिए मुख्यधारा में एक मजबूत स्थान सुनिश्चित करेगा।- ड्ड राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जनाब शमशाद अली ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की शान में खुशी जाहिर करते हुए यह कहा।

गुलाम मुस्तफा ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद अपने संबोधन में, मुस्लिम बंजारा समाज को आगे ले जाने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत किया। उनका विजन मुख्य रूप से शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे पाँच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। मुस्तफा का मानना है कि शिक्षा ही समाज के पिछड़ेपन को दूर करने की कुंजी है। उन्होंने शिक्षा क्रांति का नारा दिया है, जिसके तहत निम्नलिखित प्रमुख पहल की जाएंगी-

बंजारा छात्रवृत्ति कोष (ब्ब्व)- मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का छात्रवृत्ति कोष स्थापित करना, ताकि उच्च शिक्षा (इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रशासनिक सेवा) में उनकी पहुँच सुनिश्चित की जा सके। गुलाम मुस्तफा का मानना है कि अखिल भारतीय मुस्लिम बंजारा एकता समाज को केवल एक कल्याणकारी संगठन नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी शक्ति बनना होगा। हम अब हाशिए पर नहीं रहेंगे। मेरा लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में मुस्लिम बंजारा समाज को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में मजबूती से स्थापित करना है। हर बंजारा परिवार को वह सम्मान, शिक्षा और आर्थिक स्थिरता मिलनी चाहिए जिसका वह हकदार है। मैं केवल अध्यक्ष नहीं, बल्कि समाज के हर सदस्य का सेवक हूँ।- गुलाम मुस्तफा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा कहा। अपने कार्यकाल के पहले छह महीनों में, मुस्तफा ने प्रत्येक राज्य इकाई के साथ बैठकें आयोजित करने और उपरोक्त योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक %टास्क फोर्स% बनाने की घोषणा की है। इस कार्यबल में युवा, शिक्षित पेशेवर और अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे।

गुलाम मुस्तफा का चुनाव अखिल भारतीय मुस्लिम बंजारा एकता समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उनके व्यापक और दूरदर्शी विजन ने समाज में एक नई ऊर्जा और आशा का संचार किया है। 42 मतों की निर्णायक जीत यह दर्शाती है कि समाज उनके नेतृत्व में बड़े बदलाव और तीव्र विकास के लिए तैयार है। यह देखना बाकी है कि नया नेतृत्व इस व्यापक रोडमैप को कितनी कुशलता से लागू करता है, लेकिन फिलहाल बंजारा समाज एक उज्ज्वल और सशक्त भविष्य की उम्मीद में खुशी मना रहा है।

# मुस्लिम लीग और जिन्ना के दबाव में वंदे मातरम का बंटवारा हुआ- पीएम मोदी

नई दिल्ली ।

लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हुई चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा, संकल्प और राष्ट्र जागृति का स्रोत है. उन्होंने कहा कि जिस जयघोष ने देश को आजादी तक पहुंचाया, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना गौरव और कर्तव्य दोनों है.पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि वंदे मातरम की यात्रा 1875 में शुरू हुई और इस गीत ने भारत की स्वाधीनता लड़ाई को वैचारिक और आध्यात्मिक नेतृत्व दिया. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने भारतीयों को यह अहसास कराया कि यह लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि मां भारती की मुक्ति के लिए थी.

**कांग्रेस मुस्लिम लीग के आगे झुकी- पीएम**

अपने भाषण के निर्णायक हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम को विवाद में घसीटने का दोष इतिहास में दर्ज है. उन्होंने आरोप लगाया कि 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा विरोध किए जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के दबाव के आगे झुकते हुए वंदे मातरम की समीक्षा शुरू करवाई. पीएम मोदी ने कहा,जिन्ना के विरोध के पांच दिन बाद ही नेहरू ने पत्र लिखकर कहा कि यह गीत मुस्लिमों को भड़काता है. और यहीं से इस पवित्र गीत को दो हिस्सों में बांट दिया गया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसे सामाजिक सौहार्द का नाम दिया, लेकिन वास्तव में यह तुष्टिकरण की राजनीति थी, जिसने राष्ट्र भावना को चोट पहुंचाई और अंततः भारत के विभाजन की मानसिकता को जन्म दिया.

**सावरकर से गांधी तक, पूरा भारत वंदे मातरम की भावना में एक था- पीएम मोदी**

पीएम मोदी ने बताया कि इस गीत ने सिर्फ आंदोलन नहीं जन्मा, बल्कि स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय चेतना का आधार बनाया. उन्होंने बताया कि वीर सावरकर ने लंदन के इंडिया हाउस में यह गीत गाया, भीकाजी कामा ने फ्रांस में अखबार इसी नाम से निकाला और महात्मा गांधी ने 1905 में लिखा - वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय गीत की तरह लोकप्रिय हो गया है. उन्होंने कहा कि रवींद्रनाथ टैगोर ने भी इस गीत को भारत की एकता और बलिदान की धड़कन बताया था.

**राष्ट्र की चेतना का मंत्र है वंदे मातरम- पीएम मोदी**

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहा है, तब वंदे मातरम को नए संकल्प के रूप में स्वीकार करने की जरूरत है. उन्होंने कहा, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए वंदे मातरम के रंग स्वीकार करने का यह पावन पर्व है. इसे सिर्फ याद नहीं, जीना होगा.अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को यह सच बताया जाना जरूरी है कि जिसने स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी, उसी वंदे मातरम को राजनीतिक समझौते और दबाव में विभाजित कर दिया गया.

# 'नेताजी-टैगोर की कद्र नहीं करते...' वंदे मातरम बहस पर सीएम ममता बनर्जी का भाजपा पर तीखा हमला



नई दिल्ली । संसद में वंदे मातरम को लेकर चल रही तीखी बहस के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सवाल किया कि अगर भाजपा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रवींद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों और विचारकों की सराहना नहीं करती, तो आखिर करती किसकी है?, ममता बनर्जी ने कहा मैंने सुना कि भाजपा के कुछ लोग कह रहे हैं कि वे नेताजी की सराहना नहीं करते। तो बताइए, आप नेताजी, टैगोर और राजाराम मोहन राय को सम्मान नहीं देते, फिर किसे देते हैं? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में हुए भगवद्गीता पाठ कार्यक्रम में न जाने के फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि वह इसलिए नहीं गईं क्योंकि यह कार्यक्रम भाजपा से जुड़ा हुआ था। सनातन संस्कृति संसद की ओर से रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में लाखों लोग पहुंचे थे, जिसे 2026 विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू पहचान के बड़े प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा अगर कार्यक्रम निष्पक्ष होता, तो मैं जरूर जाती। मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ी हूं और एक विचारधारा का पालन करती हूं। मैं हर धर्म और हर समुदाय का सम्मान करती हूं। लेकिन जिस कार्यक्रम से भाजपा सीधे जुड़ी हो, उसमें मैं कैसे जा सकती हूं? उन्होंने कहा मैं ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होती जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान होता हो या महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन न किया जाता हो। मेरे माता-पिता ने मुझे यह शिक्षा नहीं दी है। जो लोग बंगाल का अपमान करते हैं, बंगला-विरोधी हैं, मैं उनके साथ नहीं हूं। लोकसभा में वंदे मातरम पर चल रही बहस के दौरान कांग्रेस उपनेता गौरव गोगोई ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन पीएम मोदी हर चर्चा में नेहरू और कांग्रेस का नाम लेते रहते हैं। गोगोई ने डेटा पढ़ते हुए कहा कि मोदी अपने भाषणों में नेहरू का नाम कई बार दोहराते हैं, चाहे 75वें संविधान दिवस की चर्चा हो या राष्ट्रपति के अभिभाषण नेहरू जी का नाम बार-बार लिया जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश की असली समस्याओं सुरक्षा, आतंकी घटनाओं और प्रदूषण पर सरकार चुप है।

# इंडिगो संकट- 7वें दिन 500+ फ्लाइट कैंसिल

**राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्री बोले- सख्त एक्शन लेंगे**

नई दिल्ली । देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं सोमवार को भी पटरी पर नहीं लौट सकीं हैं। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद एयरपोर्ट से अब तक 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी थीं। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा- हालात रोज बेहतर हो रहे हैं। 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है।

राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो संकट उसके क्रू रोस्टरिंग और इंटरनल प्लानिंग सिस्टम में समस्याओं के कारण हुआ। इससे यात्रियों को काफी दिक्कतें हुईं। हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। जांच जारी है। हम ऐसा एक्शन लेंगे जो दूसरों के लिए मिसाल बने।

इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें इंडिगो की फ्लाइट के अंदर कबूतर उड़ता दिखाई दे रहा है। ये फ्लाइट बेंगलुरु से वडोदरा जा रही थी। इधर, सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भारत सरकार पहले ही इस मुद्दे पर एक्शन ले चुकी है। मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

# घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज; सीएम योगी ने की अपील, कहा- सतर्क रहें... पहले पूछे पहचान

लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से अपील की कि वे सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले उसकी पहचान अवश्य सत्यापित करें। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त एवं निर्णायक अभियान चलाया जा रहा है।

**घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं**

मुख्यमंत्री ने यह अपील ऐसे समय में की है, जब उनके निर्देश पर पिछले सप्ताह से पूरे प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। उन्होंने सोमवार सुबह 'एक्स पर एक पोस्ट में उच्चतम न्यायालय की हालिया टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा, ''उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता। इससे स्पष्ट है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हैं।

**संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है: योगी**

सीएम योगी ने कहा कि संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राज्य की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध सघन अभियान शुरू किया गया है तथा सभी शहरी स्थानीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संसाधनों पर अनधिकृत बोझ हटाना आवश्यक है और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को वंचितों तक पहुंचने से रोका नहीं जा सकता, इसी उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है और पहचाने गए घुसपैठियों को आगे की कार्रवाई के लिए निरुद्ध केंद्र भेजा जा रहा है।

**राज्य की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है**

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मंडल में ऐसे केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जनता से अपील करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घरेलू या व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले उसकी पहचान अवश्य सत्यापित करें। उन्होंने कहा, राज्य की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि की नींव है। उच्चतम न्यायालय ने भारत में रह रहे रोहिंग्या को लेकर कानूनी स्थिति पर सवाल उठाते हुए दो दिसंबर को पूछा था कि जब देश के अपने नागरिक ही गरीबी से जूझ रहे हैं, तो घुसपैठियों को लाल कालीन बिछाकर स्वागत क्यों दिया जाए।

**बंगाल में मतदाता सूची की गहन जांच**

# चुनाव आयोग ने पांच वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को बनाया विशेष पर्यवेक्षक

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर को और पारदर्शी व सख्त निगरानी वाली बनाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने राज्य के अलग-अलग डिवीजनों में पांच वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, ताकि मतदाता सूची से जुड़े सभी काम नियमों के हिसाब से हों और किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। सोमवार को जारी आदेश में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि ये पांचों अधिकारी अपने-अपने डिवीजनों में एसआईआर से जुड़े सभी कामों की सीधी निगरानी करेंगे। आयोग की मान्यता है कि इन अधिकारियों की मौजूदगी से मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया और भरोसेमंद, साफ और निष्पक्ष बनेगी। इनके जरिए जिला अधिकारियों और रोल अधिकारियों को जरूरी सुधार और दिशा-निर्देश भी मिलते रहेंगे।

# सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर; कब से शुरू होगा शीतकालीन सत्र?

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने हरियाणा कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। आज की कैबिनेट में 21 एजेंडे रखे गए, जिसमें 19 मंजूर हुए हैं। कैबिनेट में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने की सहमति बनी है। सीएम नायब सैनी ने कहा 6 जिलों के कई गांवों की तहसील बदली गई है। कई गांवों को एक तहसील से दूसरे तहसील में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी गई है। लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार मांग आ रही थी, उनके दिए गए प्रतिवेदनों पर एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया हुआ है। कमेटी ने इन गांवों के तहसील से दूसरे तहसील में बदलने को मंजूरी दी है।

# संसद में गूंजा इंडिगो संकट का मुद्दा, कांग्रेस सांसद ने सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में आज इंडिगो परिचालन संकट का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इंडिगो परिचालन में आए व्यवधान के कारण यात्रियों को हो रही परेशानी का उल्लेख करते हुए कहा, सरकार को संसद के पटल से ये बताना चाहिए कि संकट का समाधान करने की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है। गौरव गोगोई ने प्रश्नकाल समाप्त होने के ठीक बाद इंडिगो का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि विमानन मंत्रालय इस संकट से निपटने के लिए क्या उपाय कर रहा है? गोगोई को स्पीकर ओम बिरला ने आश्वस्त किया कि केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सदन में आकर इस पर जवाब देंगे। आज वे लोकसभा में मौजूद नहीं हैं। लोकसभा में इसके बाद वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम मोदी के बाद इस विषय पर गोगोई ने भी भाषण दिया। इसके बाद विमानन परिचालन में संकट का मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया गया। दिल्ली हवाईअड्डे पर एएमएसएस में खराबी और बीते एक हफ्ते से इंडिगो के परिचालन संकट से उपजे दयनीय हालात से जुड़े सवाल पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, सरकार इस क्षेत्र में और कंपनियों के शामिल होने की की पक्षधर है। तमिलनाडु से निर्वाचित एआईएडीएमके सांसद एम थंबीदुरई ने कहा, बीते छह दिनों में जो हालात पैदा हुए हैं, इससे निपटने के लिए सरकार को और गंभीर प्रयास करने चाहिए थे। उन्होंने अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट्स पर नाराजगी जताते हुए कहा, सरकार ने यात्रियों के किराये लौटाने की बात कही है, लेकिन एअर इंडिया के विमानों में 25 हजार रुपये वसूले गए। किराये पर अंकुश क्यों नहीं है? इस चिंता पर केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, सांसदों के साथ-साथ आम लोगों को हुई असुविधा के लिए सरकार को खेद है। उन्होंने कहा कि बीते दो-तीन दिनों में जितने भी लोगों ने यात्राएं की हैं, उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी है, जिसका उन्हें दुख है। नायडू ने बताया कि 5,86,705 लाख करोड़ पीएनआर रद्द कराए गए यानी इतने विमान टिकट पर बुकिंग कराने वाले लोगों को अपनी यात्राएं टालनी पड़ीं। उन्होंने कहा कि इस एवज में 569 करोड़ रुपये रिफंड किए जा चुके हैं। दिशानिर्देशों, नियमों और गाइडलाइंस का जिक्र करते हुए नायडू ने कहा कि जहां भी उल्लंघन हुए हैं, सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। दोषियों को दंड दिया गया है। इंडिगो के विशेष संकट पर नायडू ने कहा, सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों और यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किराये में बढ़ोतरी का संज्ञान लेते हुए सरकार ने सीमा तय कर दी है। सीमित संख्या में उड़ानों की उपलब्धता के कारण थोड़ी परेशानी अभी भी हो रही है, लेकिन सरकार लगातार नजर रख रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि यात्रियों का उत्पीड़न नहीं हो सरकार इस बात का पूरा ध्यान रख रही है।